सामाजिक संस्था सम्पूर्णा
समग्र विकास की ओर अग्रसर
गैर सरकारी संगठन

आलेख

प्रधानमंत्री मोदी जी की 'तपस्या' के दो दशक

एक निर्धन परिवार में जन्म से लेकर भारत के प्रधान मंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी जी की जीवन यात्रा भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को परिभाषित करती है। यह केवल एक संयोग नहीं था जिसने मोदी जी को प्रधान मंत्री के सर्वोच्च पद तक पहुँचाया, बल्कि वर्षों के कड़े परिश्रम, सेवा और बलिदान का ही परिणाम है जिसने उन्हें आगे की लंबी यात्रा के लिए तैयार किया। 7 अक्टूबर 2021 को, वे सरकार के निर्वाचित मुखिया के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। मोदी युग के इन दो दशकों में भारतीय राजनीति और शासन में मजबूत और रचनात्मक बदलाव आए हैं।

जब से उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तभी से उन्हें असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने इन सभी चुनौतियों का सामना दृढ़ निश्चय, सहानुभूति और उत्साह के साथ किया। उनके लिए पहली चुनौती गुजरात में भूकंप के कारण हुई भारी तबाही के रूप में आई। उन्होंने लोगों के जीवन के पुनर्निर्माण के लिए खुद को समर्पित कर दिया और इसे गुजरात को विश्व स्तरीय निवेश गंतव्य में बदलने के लिए नींव रखने के अवसर के रूप में लिया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शासन में कुछ नवाचारों की शुरुआत की, जो प्रधान मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में भी अच्छी तरह से जारी रहे जिसके के कारण सरकार के कामकाज के तौर तरीकों में एक व्यवस्थित बदलाव आया है।

मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, नरेंद्र मोदी जी ने प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की जो समावेश को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ जन सामान्य की पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित थे। 'स्वागत'(SWAGAT) पहल के तहत, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी महीने में एक बार लोगों के साथ बातचीत करते थे, ताकि उनके मुद्दों को एक ही दिन में हल किया जा सके। लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ जुड़ते थे। उनके द्वारा प्रारम्भ किए गए इस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों को सरकार तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए सर्वोत्तम पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। प्रधान मंत्री पद संभालने के बाद, मोदी जी ने एक बहुउद्देश्यीय और बहु-मोडल प्लेटफार्म प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) लॉन्च किया। प्रत्येक सत्र के दौरान, प्रधान मंत्री विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हैं ताकि उनके त्वरित कार्यान्वयन में आ रही किसी भी कमियों या खामियों को दूर किया जा सके। इसकी शुरुआत के बाद से, 37 सत्र आयोजित हो चुके हैं जिनमे करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा, समाधान और कार्यान्वयन किया गया है।

विकास को जन आंदोलन में बदलने की प्रधान मंत्री मोदी की दृष्टि का पता गुजरात में उनके मुख्य मंत्री

के दिनों से लगाया जा सकता है।मुख्य मंत्री के रूप में, उन्होंने हर साल तीन दिन उन गांवों में बिताने की शुरुआत की, जहां साक्षरता दर कम थी और लोगों को बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर स्कूल में उनके लिए अलग शौचालय बनाने के उनके कदम से आगे चलकर और समर्थन मिला। उन्होंने गुजरात में बिजली क्षेत्र के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने के लिए ज्योतिग्राम योजना की शुरुआत की। सभी गांवों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए उन्होंने एक हजार दिन का लक्ष्य रखा। वर्ष 2006 में, गुजरात शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया था। उन्होंने गुजरात के किसानों के साथ मिलकर जल संकट को हल करने, कृषि पद्धतियों में प्रौद्योगिकी को जोड़ने और कोल्ड चेन बनाकर उनका समर्थन किया जिसने किसानों की उपज को विविधता प्रदान की और उनके लिए बाजारों की उपलब्धता विस्तृत हुई।

वर्ष 2014 के बाद, प्रधान मंत्री मोदी जी को सामाजिक परिवर्तन के लिए अपने दृष्टिकोण को लागू करने के लिए दायरा बढ़ा, जिससे 'जन आंदोलन' उनके प्रशासनिक मॉडल का एक अभिन्न अंग बन गया। स्वच्छ भारत मिशन से लेकर कोविड -19 के खिलाफ भारत की जंग तक, जनता से जुड़ने की उनकी अनूठी शैली उनकी सभी प्रमुख योजनाओं और पहलों में स्पष्ट झलकती है।

हर मोर्चे पर, नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्य मंत्री के रूप में और अब प्रधान मंत्री जो कहा उसे करके दिखाया है। मुख्य मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही उन्होंने विभाजन की राजनीति को त्याग दिया और सभी के लिए विकास की बात कही. प्रधान मंत्री के रूप में, उन्होंने अपनी नीतियों में इस आदर्श को और मजबूत किया और पंक्ति के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक सुविधाओं की पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए गैर-पक्षपातपूर्ण सेवा वितरण प्रणाली बनाई।

अगर वाइब्रेंट गुजरात समिट ने गुजरात को वैश्विक निवेशकों के एक आकर्षण के रूप में पेश किया, तो 'मेक इन इंडिया' वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को महत्वपूर्ण मजबूती प्रदान करने में सहायक रहा है। कोरोना महामारी के दौरान, भारत ने अपनी बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पीपीई किट, एन 95 मास्क के उत्पादन और निर्यात के लिए अपनी विनिर्माण क्षमताओं के विस्तार किया है। यहां तक कि जरूरतमंद लोगों को आवश्यक चिकित्सा सामग्री आपूर्ति करने के लिए विश्व के दूसरे देशों की भी सहायता की। महामारी के बाद की दुनिया में, वैश्विक श्रृंखलाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है और उसके लिए भारत खुद को एक लाभकारी स्थिति में पाता है, क्योकि अब एक ऐसी सरकार है जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के फलने-फूलने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर केंद्रित है।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था में कमियों के साथ-साथ जमीनी हकीकत को समझने में काफी समय लगाया। उन्होंने शासन तंत्र के हर पहलू का गहराई से अध्यन किया, और वर्षों से बाधक बनी जड़ता को दूर करने के लिए नवीनतम से नवीनतम, प्रौद्योगिकी संचालित, समग्र समाधान उपलब्ध करवाये ताकि आम जनता को उनका पूरा लाभ मिल सके। वे प्रधान मंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व इन सुधारों को एक दशक तक अमल में ला चुके थे। यह 20 वर्षों की उनकी 'तपस्या' ही है जो भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए राष्ट्रीय पुनर्जागरण की ओर ले जा रही है।